हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 128 लखनऊ, रविवार 28 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

यूपी पुलिस आज अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का बनी है प्रतीक : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में साझा किया स्मार्ट पुलिसिंग का विजन

मुख्यमंत्री योगी बोले: साढ़े आठ वर्षों में यूपी पुलिस की छवि, संरचना और कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन

सम्मेलन में बीट पुलिसिंग से साइबर सुरक्षा तक तकनीक आधारित पुलिसिंग पर व्यापक मंथन

डेटा आधारित, वैज्ञानिक और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग पर मुख्यमंत्री योगी का रहा फोकस

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन–2025 'पुलिस मंथन' का शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपने सम्बोधन में यूपी पुलिस के अब तक के कार्य, सुधार और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन और कानून–व्यवस्था की छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों से उत्तर प्रदेश को आज देश–दुनिया में एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है और परिवर्तन की यह पहचान जनता के अनुभवों से सिद्ध होती है, न कि आत्मप्रशंसा से। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग का विजन साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक पुलिसिंग के हर स्तर पर व्यापक बदलाव हुए, भर्ती, प्रशिक्षण, अवसंरचना, तकनीक, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक क्षमता, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, UP–112, सेफ सिटी मॉडल, महिला पुलिस भर्ती, और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की दिशा में निर्णायक प्रगति की गई है। पहले जहां प्रशिक्षण क्षमता सीमित थी, वहीं आज बड़े पैमाने पर 60,000 से अधिक आरक्षियों का प्रशिक्षण प्रदेश के अन्दर ही कराया जा रहा है। 75 जनपदों में साइबर थाने, 12 एफएसएल लैब और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जैसे संस्थागत बदलाव प्रदेश की नई सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास व सम्मान का भाव स्थापित कर रही है। पुलिस की भूमिका अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रो–एक्टिव और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की ओर बढ़ चुकी है। उनके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने, नवाचार अपनाने और समयबद्ध व बिंदुवार कार्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अंत में मुख्यमंत्री योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह दो दिवसीय पुलिस मंथन कार्यक्रम नीति, रणनीति और बेहतर क्रियान्वयन के जरिए समग्र पुलिसिंग को नई दिशा देगा और यूपी पुलिस अपने कार्यों को उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मेलन में दो दिन उपस्थित रहकर मार्गदर्शन देने हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के गरिमामयी इतिहास में यह एक विशिष्ट क्षण है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस मंथन में सहभागिता की है। उनकी उपस्थिति यह भरोसा देती है कि राज्य नेतृत्व पुलिसिंग की चुनौतियों को समझता है, सुधार की प्रक्रिया में मार्गदर्शक है और परिणामों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न सत्रों की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस की परिवर्तनकारी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने भर्ती, प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना, तकनीक–आधारित नागरिक सेवाओं, फॉरेंसिक सुदृढ़ीकरण, cyber policing, मिशन शक्ति केन्द्र, विशेष इकाइयों के गठन तथा अपराध के प्रति zero tolerance नीति के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य प्रत्येक सत्र से स्पष्ट उत्तरदायित्व, निर्णयों की स्पष्ट timeline और ठोस परिणाम सुनिश्चित करना है, ताकि यह मंथन कक्षों से निकलकर फील्ड में दिखाई दे और नागरिकों तक बेहतर, responsive एवं citizen–first police service पहुँचे। सम्मेलन के प्रथम दिवस कुल 07 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक सत्र के 07 नोडल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। शनिवार को आयोजित सत्रों का सार सत्र– 01 में Beat Policing विषय के नोडल अधिकारी एस०के० भगत, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा बीट पुलिसिंग से सम्बन्धित समस्या तथा उसके समाधान एवं Best practices के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यक्ष ऐप का लोकार्पण किया गया। 'यक्ष ऐप'– AI और Big Data Analysis की सहायता से तैयार किये गये बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है। इसके माध्यम से बीट पर अपराध, अपराधियों तथा संवेदनशील क्षेत्रों का समग्र डाटा उपलब्ध होगा, जिससे पुलिस कार्यवाही अधिक तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं लक्षित रूप में की जा सकेगी। यह ऐप बीट कर्मियों के रोजमर्रा के कार्यों को आसान, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में भी मददगार होगा।

सत्र– 02 में Crime Against Women, Children and Human Trafficking विषय की नोडल अधिकारी पद्मजा चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित प्रमुख कार्य, उपलब्धियां, चुनौतियां एवं भावी कार्ययोजना जिसमें नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्र, समुदाय स्तर पर किये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम एवं पारिवारिक विघटन के साथ लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालिकाओं की देखभाल एवं संरक्षण, मिशन–शक्ति के द्वारा महिलाओं एवं बाल–सुरक्षा, मिशन–शक्ति केन्द्र के द्वारा सकारात्मक बदलाव, Family Dispute Resolution Clinic (FDRC), एवं बलात्कार के प्रकरणों में कानून प्रवर्तन पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन अशोक मुथा जैन द्वारा बहू–बेटी सम्मेलन पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। सत्र– 03 में Police Station Management and Upgradation विषय के नोडल अधिकारी सुजीत पांडेय, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा थाना स्तर की पुलिसिंग में तकनीकी उन्नयन हेतु स्मार्ट एसएचओ डैशबोर्ड की विशेषताओं और उपयोगिताओं के साथ साथ इसको लागू करने के सम्बन्ध में आने वाली चुनौतियों तथा समाधान आदि के बारे में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उक्त एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से थाना प्रभारी सभी प्रमुख कार्यों पर नियंत्रण रख सकते है। इस डैशबोर्ड के क्रियान्वयन से नागरिक शिकायतों के समाधान के समय में भारी कमी, पुलिस कर्मियों के बीच जवाबदेही में वृद्धि, यातायात प्रवाह में सुधार और अपराध निगरानी में तेजी आयेगी। सत्र– 04 में Cyber Crime विषय के नोडल अधिकारी श्री बिनोद कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा बढ़ रहे साइबर अपराध के प्रमुख कारणों, साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली इत्यादि की जानकारी देने के साथ–साथ साइबर अपराध की चुनौती से निपटने के लिए साइबर थाने व साइबर हेल्प डेस्क द्वारा किये जाने वाले प्रयासों तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) के सहयोग से Capacity Building हेतु किये जा रहे प्रयासों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। सत्र– 05 में Human Resource Development, Welfare, Police Behavior and Training विषय के नोडल अधिकारी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, राजीव सभरवाल के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार हेतु विशेषज्ञ एजेंसियो के माध्यम से कराए गए प्रयास एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० प्रान्तीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग के अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं एवं उसके निवारण, उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों एवं उनके आश्रित परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं जागरूकता हेतु वामासारथी द्वारा किये जा रहे सराहनीय प्रयासों एवं प्रचलित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, भारत सरकार के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म–i–GOT पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के पुलिसबल को प्रशिक्षण कोर्स कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

सत्र– 06 में Prosecution and Prisons विषय के नोडल अधिकारी दिपेश जुनेजा, पुलिस महानिदेशक, अभियोजन के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा विभिन्न अपराधों की मॉनिटरिंग हेतु ई–रिपोर्टिंग पोर्टल को विकसित किए जाने, चिन्हित माफिया की प्रकरणवार मॉनिटरिंग हेतु डेडीकेटेड डैशबोर्ड बनाए जाने, नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु डेडीकेटेड डैशबोर्ड बनाए जाने, अभियोजकों के दैनिक कार्यों के मूल्यांकन हेतु ई–प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर 12 के०पी०आई० निर्धारित किए जाने, पेपरलेस व्यवस्था में अभियोजन द्वारा मानव संपदा पोर्टल, ई–ऑफिस तथा ई–प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर कार्य किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अतिरिक्त डीजी कारागार प्रेम चन्द मीना द्वारा उत्तर प्रदेश की कारागारों का डिजिटलीकरण, डिजिटल तकनीक से पारदर्शिता, सुरक्षा, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, बंदियों का सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माननीय न्यायालय में 50,000 से अधिक गवाही कराये जाने, AI आधारित सीसीटीवी निगरानी, ई–मुलाकात, हेल्थ ए.टी.एम., डिजिटल लाइब्रेरी, समय पूर्व रिहाई सॉफ्टवेयर, ई–अभिरक्षा प्रमाणपत्र आदि नवाचारों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। सत्र– 07 में CCTNS 2.0, Nyay Sanhita and Forensics विषय के नोडल अधिकारी नवीन अरोड़ा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा बढ़ते अपराधों की जटिलता, साइबर अपराधों में वृद्धि तथा नागरिकों की त्वरित न्याय की अपेक्षाओं के दृष्टिगत पुलिसिंग को अधिक डेटा–आधारित, वैज्ञानिक एवं नागरिक–केंद्रित बनाये जाने, CCTNS के माध्यम से पुलिस रिकॉर्ड, FIR एवं विवेचना से संबंधित डेटा का एकीकरण एवं नई न्याय संहिताओं के अंतर्गत e-FIR, Zero FIR, e-Summon एवं e-Sakshy जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के समापन उद्बोधन से प्रथम दिवस का सम्मेलन समाप्त हुआ।

तीन को डिजिटल अरेस्ट करके एक करोड़ से ज्यादा वसूले, एक माह तक करते रहे व्हाट्सएप कॉल, सात दिन रखा कैद

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। साइबर जालसाजों ने दो बुजुर्गों और एलडीए में तैनात महिला कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ आठ लाख रुपये वसूल लिए। दो बुजुर्गों ने साइबर क्राइम थाने और महिला ने इंदिरानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ठगों का पता लगा रही है। खाते से ट्रांसफर करवा लिए 30 लाख रुपये राजाजीपुरम निवासी बुजुर्ग महालक्ष्मी श्रीवास्तव के मुताबिक 24 नवंबर को उनके पास अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अफजल खान के पास से उनका आधार कार्ड मिला है। पहलगाम हमले में पकड़े गए आतंकवादी हाफिज फौजी ने बयान दिया है कि उसने आपके बैंक खाते में 70 लाख रुपये भेजे हैं। इसके एवज में आपने देश के खिलाफ जानकारी साझा की है। महालक्ष्मी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोषी पाए जाने की बात कहते हुए जेल भेजने की धमकी दी गई। झांसे में लेने के लिए एटीएस के कथित अफसर से बात कराई। उसने भी महालक्ष्मी को धमकाया और मदद का झांसा देकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ठगों ने उनके खाते से 30 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। छह दिसंबर को फिर से रुपये मांगे। इस पर महालक्ष्मी को संदेह हुआ और उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सात दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट गोमतीनगर के वास्तु खंड निवासी उत्तर प्रदेश वित्त लेखा सेवा से सेवानिवृत्त राजेंद्र प्रकाश वर्मा के मुताबिक 13 दिसंबर को उनके पास फोन करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया। उसने पहलगाम हमले में गिरफ्तार आतंकी अफजल खान के प्रकरण में हाफिज फौजी के बयान का जिक्र किया। ठग ने कहा कि आपके खाते में सात

करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह लेन–देन एचडीएफसी बैंक कोलाबा मुंबई के खाते में हुआ है, जो आपके आधार कार्ड पर खोला गया है। ठग ने राजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी देते हुए जेल भेजने की धमकी दी। राजेंद्र ने कहा कि वह पेंशनर हैं और उन्होंने कोई रकम नहीं ली है। इस पर ठग ने उनकी एटीएस के कथित अफसरों से बात कराई। इसके बाद ठगों ने उनके सारे बैंक खातों की जानकारी ले ली। फिर सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 54.68 लाख रुपये वसूल लिए। 19 दिसंबर को ठगों ने दबाव बनाने के लिए पास के थाने जाकर पुलिसकर्मियों से बात कराने के लिए कहा। पीड़ित जब थाने पहुंचे तो उन्हें ठगी की जानकारी हुई। एक माह तक करते रहे व्हाट्सएप कॉल इंदिरानगर के तकरोही निवासी एलडीए में कनिष्ठ लिपिक ज्योति सिंह से साइबर अपराधियों ने 23.33 लाख रुपये वसूल लिए। पीड़िता के मुताबिक 28 नवंबर को उनकी शादी की सालगिरह पर अंजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने अपना नाम वीरेंद्र बताते हुए उन्हें पार्सल भेजने की बात कही। इस पर ज्योति ने इन्कार कर दिया। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को पार्सल वाला बताया। ज्योति ने पार्सल लेने से मना करते हुए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले दिन खुद को सीबीआई अफसर बताकर एक व्यक्ति ने फोन किया और पार्सल रिसीव करने का दबाव बनाया। फिर जेल भेजने की धमकी दी। करीब एक माह तक जालसाज व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से ज्योति से बात करते रहे। उन पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए थे प्रतापगढ़ के 53 मजदूर, पुलिस ने किया रेस्क्यू

एजेंसी

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले मे बंधक बनाये गये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी समुदाय के तेरह महिलाओं सहित 53 लोगों को छुड़ाकर लाया गया है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने शुक्रवार देर रात प्रतापगढ़ में मीडिया को यह जानकारी दी। आदित्य ने बताया कि गत 22 दिसंबर को सूचना मिली थी कि जिला प्रतापगढ़ के घण्टाली, पीपलखूँट, पारसोला थाना क्षेत्र के ग्राम वरदा, जामली, मालिया, गोठड़ा, उमरिया पाड़ा, बड़ा काली घाटी, ठेसला एवं कुमारी तथा अन्य गांवों के महिला एवं पुरुष जिनको मजदुरी के लिये महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पुलिस थाना अकलूज क्षैत्र के जाबुड़ गांव मे मजदुरी के लिये स्थानीय व्यक्ति की मदद से करीब दो महीने पूर्व ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि मजदूरी के लिए गये व्यक्तियों ने कुछ समय बाद अपने परिजनों से जरिये फोन वार्ता करते हुए बताया कि उनके साथ मजदुरी के लिये लेकर जाने वाले दलाल सीताराम पाटिल (महाराष्ट्र) व अलवर राजस्थान के खान नामक व्यक्ति एक स्थानीय व्यक्ति ने प्लानिंग बना कर इन्दौर मध्यप्रदेश मे प्रति व्यक्ति 500 रूपये मजदुरी दिलाने व खाना व रहना फ्री होने का झांसा देकर करीब 100 लोगों को महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अकलूज थाना क्षैत्र मे जाबुड़ गांव लेकर गये। जहां पर तीनों व्यक्तियों ने योजना बनाकर सभी को अलग – अलग जमीदारों के पास गन्ने के खेतों मे मजदुरी के लिये रख दिया। अलवर राजस्थान के दलाल खान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के जमीदारों से मजदुरों की मजदुरी के साढ़े नौ लाख रूपये एडवांस लेकर अलवर आ गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र दलाल सीताराम पाटिल ने भी जमीदारों से 18 लाख रूपये एडवांस मजदूरी के तौर पर ले लिये। बाद में जमीदारों के द्वारा मजदुरी के लिए गये व्यक्तियों के द्वारा अपनी मजदुरी के रूपये मांगने पर दलाल सीताराम पाटिल एवं अन्य जमीदारों के द्वारा मजदूरों पर अत्याचार शुरू कर दिया एवं गन्ने के फार्म हाउस पर बने मकान एवं बाड़ों मे बंधक बनाकर जबरन काम कराया जाने लगा। जिससे परेशान होकर मौका मिलने पर कई मजदूर उनके चुंगल से छूटकर भागकर वापस आ गये।

केजीएमयू में धर्मांतरण का प्रयास : महिला आयोग को भेजी गई रिपोर्ट, डॉक्टर के मददगारों की जांच के लिए समिति गठित

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। केजीएमयू में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के धर्मांतरण के प्रयास मामले में जांच रिपोर्ट महिला आयोग भेज दी गई है। इसके साथ ही विविप्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट की मदद करने वालों की पहचान के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने विभाग के ही एक पुरुष रेजिडेंट पर उनकी बेटी का धर्मांतरण कराने के प्रयास का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य महिला आयोग को भेजी गई थी। इससे पहले रेजिडेंट ने 17 दिसंबर को नशीली गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था। इस मामले में चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। राज्य महिला आयोग ने इस मामले में केजीएमयू से जवाब मांगा था। केजीएमयू प्रशासन ने मीडिया से मिली सूचना के आधार पर मामला विशाखा समिति के सामने रखा। समिति ने आरोप सही पाते हुए आरोपी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट राज्य महिला आयोग के पास भेज दी गई है। पांच सदस्यीय समिति करेगी मददगारों की पहचानरू केजीएमयू परिसर में बीते दिनों नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया था कि आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को कई लोग बचा रहे हैं। इस पर केजीएमयू प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति के अध्यक्ष पैरामेडिकल संकाय के डीन प्रो. केके सिंह हैं। एमएस प्रो. सुरेश कुमार, प्रॉक्टर प्रो. आरएएस कुशवाहा, प्रो. हैदर अब्बास और प्रो. सुमित रुंगटा भी समिति में शामिल हैं। आरोपी डॉक्टर की मां और पिता से पूछताछ रू चौक पुलिस ने आरोपी डॉ. रमीज मलिक की मां और पिता से शुक्रवार को चार घंटे पूछताछ की। दोनों ने डॉ. रमीज की महिला डॉक्टर से दोस्ती होने की बात की जानकारी से इन्कार कर दिया। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट में अवकाश होने के कारण अभी तक पीड़िता के बयान नहीं दर्ज हो सके हैं। वहीं, मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट और व्हाट्सएप डाटा का इंतजार किया जा रहा है। पीड़िता को आवंटित किया गया छात्रावास : पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए उसे परिसर में हॉस्टल आवंटित किया गया है। इससे पहले वह परिसर के बाहर किराये पर रहती थी। केजीएमयू प्रशासन ने महिला सुरक्षा गार्ड को 24 घंटे पीड़िता के साथ रहने के निर्देश दिए हैं। परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ा दिए गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

महोबा पुलिस को मिला बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

एजेंसी

महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को तड़के पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी अपराधी को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने यहां बताया कि लम्बे समय से फरार चल रहे अपराधी वारिश उर्फ लुच्ची डान के सम्बन्ध में मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ओर एसओजी की टीम ने राठ रोड पर उसकी घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस के ललकारने पर अपराधी द्वारा अपने साथ लिए असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा की गयी गोलीबारी में पैर में गोली लग जाने के कारण वारिश गिर गया. जिसके उपरान्त पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया। उन्होने बताया की वारिश के पास से 315 बोर का तमंचा व कारतूस, 95 हजार नकदी व 36 ग्राम पीली धातु बरामद की गयी है। जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा इन दिनों चलाये जा रहे।

बांग्लादेश में बढ़ता भारत विरोध, इमरान मसूद ने जताई चिंता, प्रभावी कदम उठाने की मांग

एजेंसी

सहारनपुर। बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे भारत विरोधी प्रदर्शनों और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भारतीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पड़ोसी देश की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश अब धीरे–धीरे भारत विरोध का अड्डा बनता जा रहा है और इस पर भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी हो रही है और वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्व भारत विरोध को हवा दे रहे हैं, वह न केवल भारत–बांग्लादेश संबंधों के लिए खतरनाक है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाना बेहद खराब हरकत है और इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

संपादकीय

आत्मबल का सहारा

जमाने की नजरों में हम कैसे हैं? यह जानने के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं । न ही कोई हमें यह समझा पाएगा कि हम कैसे हैं? दरअसल, बहुत संभव होता है कि कोई हमारे प्रति आग्रह या दुराग्रह रखे । ऐसी स्थिति में अपने आप से अपना वास्तविक परिचय जानने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को ही टटोलना होगा। अंतरात्मा की गवाही इस तथ्य की पुष्टि स्पष्ट रूप से कर सकेगी कि वास्तव में हम कैसे है ? निश्चित रूप से जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं, तब अंतर्मन में किसी प्रकार के बोझ से बाधित नहीं होते । जीवन एकदम सहज और सरल हो जाता है। हमारा यह स्वभाव एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को श्रृंगारित करने लगता है। हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे है ? क्या कुछ हम कर चुके और क्या कुछ हम करना चाह रहे थे ? आने वाले दौर में हम अपने आप को किस मुकाम पर लाकर खड़ा करना चाह रहे थे? क्या कुछ हम पा चुके और क्या खो चुके ? अब तक की सारी जिंदगी जमाने भर की उठापटक में गुजर गई कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया? इस तरह के तमाम सवालों का सही जवाब और किसी के एक सवाल का भी नहीं। मगर हमारी अपनी अंतरात्मा को बखूबी ज्ञात होता है। हालांकि जाहिर तौर पर हम अपने अंतर्मन की वास्तविक दशा और मनोदशा को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते। लेकिन हम क्या हैं, यह गवाही तो हमारा मन देता ही रहता है। हमारा आचार–विचार और व्यवहार हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हर किसी के बारे में मतभिन्नता बहुत स्वाभाविक होती है। बहुत संभव होता है कि कोई किसी के लिए अच्छे से अच्छा हो और किसी के लिए बुरे से बुरा हो। ऐसी स्थिति में जब हम यह मूल्यांकन करना चाहें कि हम वास्तव में क्या हैं, तब स्वयं के बारे में निष्पक्ष तथा तटस्थ अवधारणा की पुष्टि हमारी अंतरात्मा ही करती है । वास्तव में आदमी जमाने को धोखा दे सकता है और स्वयं भी धोखे में रह सकता है, लेकिन यह संभव नहीं कि कोई लंबे समय तक धोखे में रह सके। अंतरात्मा की गवाही नकारात्मक होने पर अपराधबोध और सकारात्मक होने पर आत्मबल में वृद्धि करती है । दरअसल, व्यक्ति विशेष के अंतरंग और बहिरंग में एकरूपता हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस अपेक्षा की कसौटी पर हर कोई खरा उतर सके, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता । व्यक्ति विशेष के प्रति आम धारणा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह धारणा पूर्ण रूप से सकारात्मक या पूर्ण रूप से नकारात्मक भी हो सकती है ।आजकल के जमाने में सर्वमान्य शख्सियत की परिकल्पना दिवास्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। यह बहुत संभव होता है कि नकारात्मक व्यक्ति के पक्ष में कुछ सकारात्मक बिंदु भी हों। ठीक इसी तरह सकारात्मक में भी नकारात्मकता के अंश को खोजा जा सकता है। गरज यह कि इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है । सामान्य बोलचाल में भी कहा गया है कि लोगों ने राजा राम को नहीं छोड़ा तो आप हम क्या है ! ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर एकदम सही रहें। हमारा सकारात्मक सोच– विचार तथा कार्य और व्यवहार पूर्ण रूप से सात्विक रहे । एक अर्थ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को हम खुद ही समय–समय पर तटस्थ एवं निष्पक्ष रूप से आकलित कर प्रमाणित करते रहें । यही आत्म–मूल्यांकन का सिलसिला हमारे अपने अंतर्मन की संतुष्टि का अहम कारण बन सकता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है, जिसके चलते जीवन संवर जाता है । हमारा हाव–भाव और व्यवहार भी जमाने भर को हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व के मूल्यांकन का आधार देता है । चित्त की सहजता और सरलता के मनोभाव आचार–विचार और व्यवहार से परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा, चित्त की कुटिलता का आकलन भी प्रयुक्त शब्दावली और भाव–भंगिमा के आधार पर सहज ही किया जा सकता है। दरअसल, इस सहज मनोविज्ञान को औसत स्तर के आम व्यक्ति के लिए भी समझना कोई दुष्कर नहीं है। यह निश्चित है कि जब हम सहज और सरल होते हैं, तो हमारा आत्मबल अत्यंत विकसित अवस्था में आकर सकारात्मक वातावरण का सृजन करने में प्रबल रूप से सहायक होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे अपने आसपास के परिवेश में, जान– पहचान के लोगों के बीच हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर आमतौर पर कोई न कोई धारणा अवश्य होती है । यह धारणा केवल नकारात्मक या केवल सकारात्मक ही हो, यह कतई आवश्यक नहीं होता। ऐसा भी होता है कि जमाने की निगाहों में हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति मिली–जुली धारणा हो । ऐसी स्थिति में कभी–कभी हमें संदेह का लाभ भी मिल जाया करता है। दरअसल, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हर एक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं हो सकता। हर किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आकलन में परस्पर विरोधाभास की स्थिति बहुत स्वाभाविक होती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने प्रति जनमानस में व्याप्त सकारात्मक या नकारात्मक धारणा को लेकर न तो उत्साहित होना चाहिए और न ही निराश।

राशिफल

मेष :– किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन सन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए `रित करेंगी। आलस्य कतई न करें।
बृषभ :– भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कायरें को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।
मिथुन :– भावनाओं पर नियंतण्ररख अपने दायित्वों के ति सजग होना गति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा– तियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।
कर्क :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर भावी होंगी। भौतिक–सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी कार की शिकायत पर खुलकर बात करें।
सिंह :– भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख–दुख के ति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के ति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्नक विचार ला सकती हैं।
कन्या :– नये संबंधों में गाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सु ढ़ता हेतु यत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।
तुला :– कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन–स ा की दिशा में कें ित लोगों को लाभ के अवसर ाप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।
वृश्चिक :– किसी पुराने संबंध के ति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सु ढ़ता हेतु `रित करेंगी। भावना धान मन रिश्तों से सहज ही भावित हो जाता है।
धनु :– रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ बल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।
मकर :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी ियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यि से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
कुंभ :– पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन–स ा से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर ाप्त होंगे। पूजा–पाठ में पूरा दिन मन कें ित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।
मीन :– पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का योग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से भावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

बाल तस्करी और न्याय की परीक्षा

—डॉ प्रियंका सौरभ

भारत में बाल तस्करी आज केवल एक सामाजिक विकृति नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय और संगठित आपराधिक तंत्र का रूप ले चुकी है। यह अपराध उन कमजोर सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं में जड़ें जमाता है जहाँ गरीबी, अशिक्षा, विस्थापन, लैंगिक असमानता और प्रशासनिक उदासीनता एक साथ मौजूद रहती हैं। बाल तस्करी की भयावहता केवल इस तथ्य में निहित नहीं है कि बच्चे शोषण का शिकार बनते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि यह अपराध अत्यंत कुशलता से कानून और न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं का लाभ उठाता है। इसी कारण, कड़े कानूनी प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बावजूद भारत में बाल तस्करी से जुड़े मामलों में दोषसिद्धि दर चिंताजनक रूप से कम बनी हुई है। बाल तस्करी को 'स्तरित संगठित अपराध' कहा जाना मात्र एक सैद्धांतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह इसके कार्य–तंत्र की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। इस अपराध में सामान्यतः कोई एक केंद्रीय संचालक नहीं होता, बल्कि अनेक स्वतंत्र लेकिन परस्पर पूरक इकाइयाँ कार्य करती हैं। भर्ती करने वाला व्यक्ति प्रायः स्थानीय स्तर पर सक्रिय होता है, जो बच्चों या उनके अभिभावकों को शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन या विवाह जैसे झूठे वादों के माध्यम से फुसलाता है। इसके बाद परिवहन से जुड़े एजेंट, आश्रय उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क, दस्तावेज़ों की जालसाजी करने वाले समूह और अंततः शोषण करने वाले व्यक्ति या संस्थाएँ अलग–अलग स्तरों पर सक्रिय होती हैं। इन सभी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न्यूनतम होता है, जिससे पूरे अपराध तंत्र को एक सूत्र में बाँधकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस स्तरित संरचना का सबसे बड़ा लाभ अपराधियों को यह मिलता है कि प्रत्येक कड़ी स्वयं को सीमित भूमिका तक प्रतिबंधित दिखा सकती है। कोई स्वयं को केवल 'मददगार', कोई 'दलाल', तो कोई 'नियोक्ता' बताकर अपनी आपराधिक मंशा से पल्ला झाड़ लेता है। परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष के लिए आपराधिक षड्यंत्र, साझा मंशा और संगठित अपराध को सिद्ध करना लगभग असंभव हो जाता है। यह जटिलता तब और बढ़ जाती है जब तस्करी अंतर–राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लेती है, जहाँ विभिन्न राज्यों के कानून, पुलिस तंत्र और न्यायिक प्रक्रियाएँ एक–दूसरे से समन्वित नहीं हो पातीं। आधुनिक समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने इस अपराध को और अधिक अदृश्य बना दिया है। एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गुप्त मैसेजिंग ऐप्स और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से तस्कर न केवल बच्चों की आवाजाही को नियंत्रित करते हैं, बल्कि साक्ष्यों को भी शीघ्र नष्ट कर देते हैं। इस स्थिति में पारंपरिक जाँच पद्धतियाँ अपर्याप्त सिद्ध होती हैं और अभियोजन का पूरा बोझ अंततः पीड़ित की गवाही पर आ टिकता है। यहीं से बाल तस्करी से जुड़े मामलों में साक्ष्यगत चुनौतियों की वास्तविक समस्या प्रारंभ होती है। नाबालिग पीड़ित अक्सर भय, मानसिक आघात, सामाजिक कलंक और आर्थिक निर्भरता के कारण स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं होते। लंबे समय तक चली शारीरिक और मानसिक यातना उनके स्मृति–तंत्र को प्रभावित करती है, जिसके कारण उनकी गवाही में असंगतियाँ, रिक्तताएँ और विरोधाभास स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इसके बावजूद, परंपरागत न्यायिक दृष्टिकोण में इन असंगतियों को गवाही की अविश्वसनीयता के रूप में देखा जाता रहा है। इतिहासतः भारतीय न्याय प्रणाली में तस्करी के शिकार बच्चों को कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सह–अपराधी की तरह देखा गया। विशेष रूप से यौन शोषण या अवैध श्रम से जुड़े मामलों में यह धारणा बनी कि पीड़ित ने परिस्थितियों से समझौता किया या किसी स्तर पर अपराध में भागीदारी निभाई। इस दृष्टिकोण के कारण उनकी गवाही को अतिरिक्त पुष्टिकरण की आवश्यकता बताई गई, जबकि संगठित अपराधों में स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध होना पहले से ही दुर्लभ होता है। नतीजतन, अभियुक्त संदेह का लाभ उठाकर बरी होते रहे और पीड़ित न्याय से वंचित रह गए। शिकायत दर्ज करने में देरी भी एक बड़ी समस्या रही है। सामाजिक भय, परिवार की प्रतिष्ठा, आर्थिक असुरक्षा और अपराधियों की धमकियों के कारण पीड़ित या उनके अभिभावक प्रायः लंबे समय तक चुप रहते हैं। न्यायालयों द्वारा इस देरी को संदेह की दृष्टि से देखा जाना अभियोजन को और कमजोर कर देता है। इसके अतिरिक्त, अपराध की पूरी श्रृंखला को क्रमबद्ध रूप से न बता पाना, विशेषकर तब जब अपराध कई महीनों या वर्षों तक चला हो, पीड़ित की गवाही को तकनीकी आधार पर खारिज करने का कारण बनता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाबालिगों को 'पीड़ित गवाह' के रूप में मान्यता देने का निर्देश भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक गुणात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। यह निर्देश यह स्वीकार करता है कि बाल तस्करी के शिकार बच्चे अपराध के सहभागी नहीं, बल्कि संरचनात्मक शोषण के शिकार हैं। 'पीड़ित गवाह' की अवधारणा गवाही के मूल्यांकन के पारंपरिक मानकों को मानवीय यथार्थ के साथ जोड़ती है और न्यायालयों को यह स्मरण कराती है कि आघात–ग्रस्त स्मृति पूर्णतः तार्किक या रैखिक नहीं होती। इस न्यायिक दृष्टिकोण के तहत अब यह अनिवार्य नहीं रह जाता कि पीड़ित की गवाही हर बिंदु पर पूर्णतः सुसंगत और त्रुटिहीन हो। सूक्ष्म विरोधाभास, घटनाओं के क्रम में अस्पष्टता या विवरणों में अंतर को स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, न कि झूठ या मनगढ़ंत कहानी के प्रमाण के रूप में। इससे अभियोजन को यह अवसर मिलता है कि वह अपराध की व्यापक संरचना को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और पीड़ित के कथन के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत कर सके। 'पीड़ित गवाह' का दर्जा यह भी सुनिश्चित करता है कि शिकायत में देरी को स्वचालित रूप से गवाही की कमजोरी न माना जाए। भय, सामाजिक दबाव और मानसिक आघात को न्यायिक संज्ञान में लेते हुए अब देरी को परिस्थितिजन्य वास्तविकता के रूप में समझा जाता है। यह परिवर्तन विशेष रूप से बाल तस्करी जैसे अपराधों में महत्वपूर्ण है, जहाँ पीड़ित की चुप्पी स्वयं अपराध की निरंतरता का परिणाम होती है। इसके अतिरिक्त, यह दृष्टिकोण स्मृति–लोप और विखंडित स्मृति को भी वैध मान्यता देता है। आघात के कारण उत्पन्न स्मृति–विघटन में पीड़ित को अपराध की पूरी श्रृंखला याद न रह पाना स्वाभाविक है। पहले जहाँ यह स्थिति अभियुक्त के पक्ष में जाती थी, वहीं अब न्यायालयों को यह विवेक प्राप्त होता है कि वे गवाही के मूल भाव और संदर्भ को महत्व दें, न कि केवल तकनीकी पूर्णता को। इस प्रकार, 'पीड़ित गवाह' की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया को औपचारिकता–प्रधान से पीड़ित–केंद्रित यथार्थवाद की ओर ले जाती है। यह परिवर्तन न केवल दोषसिद्धि दर बढ़ाने की क्षमता रखता है, बल्कि संगठित अपराधों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों को भी न्यायिक विमर्श में स्थान देता है। जब पीड़ित की आवाज़ को संदेह के बजाय संवेदना और समझ के साथ सुना जाता है, तभी न्याय प्रणाली अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर पाती है। फिर भी, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि केवल न्यायिक निर्देश पर्याप्त नहीं हैं। यदि 'पीड़ित गवाह' की अवधारणा को प्रभावी बनाना है, तो इसके साथ–साथ जाँच एजेंसियों की संवेदनशीलता, अभियोजकों का प्रशिक्षण, गवाह संरक्षण तंत्र और पीड़ितों का पुनर्वास भी उतना ही आवश्यक है। बिना सामाजिक–आर्थिक पुनर्स्थापन के, पीड़ित पुनः शोषण के चक्र में फँस सकता है, जिससे न्यायिक उपलब्धियाँ खोखली सिद्ध होंगी। अंततः, बाल तस्करी के विरुद्ध संघर्ष केवल कानून का प्रश्न नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय का 'पीड़ित गवाह' संबंधी निर्देश इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो यह संकेत देता है कि न्याय अब केवल प्रक्रिया का पालन नहीं, बल्कि पीड़ित के अनुभव को समझने का प्रयास भी है। यदि इस दृष्टिकोण को सशक्त संस्थागत समर्थन प्राप्त होता है, तो यह भारत में बाल तस्करी जैसे स्तरित संगठित अपराधों के विरुद्ध एक प्रभावी हथियार सिद्ध हो सकता है और न्याय की अवधारणा को वास्तव में मानवीय बना सकता है।

बांग्लादेश: सत्ता-संघर्ष, कट्टरपंथ और लोकतंत्र की अनिश्चित राह

—ललित गर्ग—

बांग्लादेश एक बार फिर इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ लोकतंत्र, सत्ता और कट्टरपंथ के बीच की रेखाएँ धुंधली होती जा रही हैं। 17 वर्षों के स्वनिर्वासन के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की स्वदेश वापसी केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि उस अस्थिरता का प्रतीक है, जो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश की राजनीति में लगातार गहराती चली गई है। यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस स्वयं कई मोर्चों पर घिरते नजर आ रहे हैं और जिन ताकतों को उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्थान दिया, वही आज शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद जिस छात्र आंदोलन को 'जुलाई क्रांति' के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उससे देश में यह उम्मीद जगी थी कि एक नई, पारदर्शी और समावेशी व्यवस्था की नींव रखी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ छात्र नेताओं और नागरिक समाज के एक बड़े वर्ग ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी। लेकिन कुछ ही महीनों में यह भ्रम टूटने लगा कि यह संघर्ष व्यवस्था परिवर्तन का है। चुनाव को लेकर बढ़ती खींचतान, स्पष्ट रोडमैप का अभाव और सत्ता के इर्द–गिर्द सिमटती निर्णय प्रक्रिया ने यह संकेत दे दिया कि अब लड़ाई लोकतंत्र को मजबूत करने की नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जे की है। इस संदर्भ में कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। हादी जुलाई आंदोलन से उभरे उन चेहरों में थे, जिनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उनकी हत्या के बाद उनके भाई द्वारा लगाए गए आरोप कि यह हत्या अंतरिम सरकार से जुड़े तत्वों की साजिश है ताकि चुनाव टाले जा सकें, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की नैतिकता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न

लगाते हैं। यदि यह आरोप सही हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि सत्ता में शामिल कुछ शक्तियां जानबूझकर देश को अस्थिरता एवं घोर अशांति की ओर धकेल रही हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया को अपने अनुकूल मोड़ा जा सके। कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में सबसे चिंताजनक है। जमात–ए–इस्लामी जैसी ताकतों का अंतरिम सरकार पर बढ़ता दबाव, सड़कों पर बढ़ती हिंसा और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कानून– व्यवस्था तेजी से कमजोर हुई है। विडंबना यह है कि जिन कट्टरपंथी तत्वों को शेख हसीना सरकार के विरोध में 'लोकतांत्रिक सहयोगी' के रूप में देखा गया, वही आज बांग्लादेश की सामाजिक संरचना को भीतर से खोखला कर रहे हैं। यह वही ऐतिहासिक भूल है, जो दक्षिण एशिया के कई देशों में पहले भी की जा चुकी है–जहां अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए कट्टरपंथ को जगह दी गई और परिणाम दीर्घकालिक अस्थिरता के रूप में सामने आया। तारिक रहमान की वापसी को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन में 17 वर्षों से अधिक समय बिताने के बाद उनका लौटना केवल व्यक्तिगत निर्वासन की समाप्ति नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए शक्ति–संतुलन का संकेत है। यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जिन मुकदमों के कारण वे देश से बाहर थे, उनमें अंतरिम सरकार के दौरान राहत मिली और उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ। जिस दिन तारिक रहमान ढाका लौटे, उसी दिन यह संकेत भी सामने आया कि शेख हसीना की अवामी लीग को आगामी चुनावों से बाहर रखा जा सकता है। यह संयोग कम और रणनीति अधिक प्रतीत होता है। बीएनपी इस समय चुनावी गणित के लिहाज से सबसे मजबूत स्थिति में है और तारिक रहमान को देश का अगला प्रधानमंत्री माने जाने की चर्चा तेज है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अवामी लीग के बिना होने वाला चुनाव बांग्लादेश की जनता की वास्तविक इच्छा को प्रतिबिंबित कर पाएगा? लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन का नाम नहीं, बल्कि सभी प्रमुख राजनीतिक धाराओं को समान अवसर देने की प्रक्रिया है। यदि किसी एक बड़े दल को सुनियोजित ढंग से बाहर रखा जाता है, तो चुनाव की वैधता पर संदेह स्वाभाविक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मोहम्मद यूनुस की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और कानून–व्यवस्था की बदहाली को लेकर मानवाधिकार संगठनों की चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके बावजूद यह आश्चर्यजनक है कि भारत जैसे पड़ोसी देश से, जहाँ बांग्लादेश के घटनाक्रम का सीधा प्रभाव पड़ता है, अपेक्षित स्तर की कूटनीतिक और नैतिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए भारत की ओर से सहयोग की पेशकश करना एक सकारात्मक संकेत है, और बीएनपी द्वारा उसका स्वीकार किया जाना दोनों देशों के बीच नए समीकरणों की ओर इशारा करता है। लेकिन यह भी सच है कि यह निकटता स्वार्थों की राजनीति से पूरी तरह मुक्त नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे हमले अब केवल आंतरिक कानून–व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गए हैं, बल्कि यह भारत की सुरक्षा, कूटनीतिक जिम्मेदारी और नैतिक सरोकार से सीधे जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। हाल ही में अमृत मंडल नामक एक हिंदू नागरिक की पीट–पीटकर हत्या की घटना इस बात का प्रमाण है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति थमने के बजाय और अधिक निर्भीक होती जा रही है। धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा, मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन और भय का वातावरण बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख को गहरा आघात पहुँचा रहे हैं। भारत सरकार के लिए अब यह अनदेखा करने का विषय नहीं रह गया है; आवश्यकता है कि वह कूटनीतिक स्तर पर सख्त संदेश दे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए और यह स्पष्ट करे कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। आगामी चुनावों के संदर्भ में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भय और असुरक्षा के वातावरण में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना ही बेमानी है। बांग्लादेश में यदि वास्तव में लोकतंत्र की बहाली का दावा किया जा रहा है, तो वहां ऐसी सरकार का गठन आवश्यक है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान की गारंटी दे सके। हिंदुओं सहित सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना न तो राजनीतिक स्थिरता संभव है और न ही क्षेत्रीय शांति। भारत की भूमिका इस संदर्भ में केवल पड़ोसी देश की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति की है, जिसे मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना होगा। बांग्लादेश आज जिस मुसीबत के भंवर में फँसा है, उसके पीछे आंतरिक कारकों के साथ–साथ बाहरी प्रभावों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की ऐतिहासिक भूमिका और कट्टरपंथी नेटवर्कों के साथ उसके संबंधों को देखते हुए यह आशंका निराधार नहीं कि बांग्लादेश की अस्थिरता में परोक्ष योगदान बाहरी शक्तियों का भी हो सकता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे अंतरिम सरकार को निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक दिशा में ले जाएँ। लेकिन अब तक के घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि वे हालात को संभालने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। फिर भी, इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच तारिक रहमान के बयानों और राजनीतिक स्वरों में कुछ लोग समाधान की झलक देखते हैं। यह उम्मीद इस विश्वास पर टिकी है कि बीएनपी, चाहे उसका अतीत विवादास्पद रहा हो, सत्ता में आकर कट्टरपंथी दबावों को संतुलित कर सकेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। किंतु यह भी एक कड़वा सत्य है कि कट्टरपंथी ताकतों से लोकतंत्र बहाल होने की उम्मीद अपने आप में एक विरोधाभास है। अंततः बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है–क्या वह एक समावेशी, बहुदलीय और संवैधानिक लोकतंत्र की राह चुनेगा या फिर सत्ता–संघर्ष और कट्टरपंथ की दलदल में और गहराता जाएगा? इसका उत्तर केवल किसी एक नेता या दल के हाथ में नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विवेक में है, जो आने वाले महीनों में देश की दिशा तय करेगा। यदि निष्पक्ष चुनाव, कानून का राज और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो तारिक रहमान की वापसी भी इतिहास में एक और चूके हुए अवसर के रूप में दर्ज हो सकती है।

मेडिकल छात्रों को डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने में सहायता करें

चिकित्सा शिक्षा बदल रही है। अतीत में, हमने शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी और नैदानिक कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया है, कम ध्यान के साथ जिसे अक्सर ष्सॉफ्ट स्किल्सष कहा जाता हैरू दबाव में लचीलापन, यह जानना कि कब नेतृत्व करना है और कब सहयोग करना है, और सहानुभूति और आत्म–जागरूकता का दोतरफा सिक्का। लेकिन केवल ज्ञान के हस्तांतरण के बजाय, आज शिक्षाविद अच्छी तरह से तैयार स्नातकों को विकसित करने के महत्व को समझते हैं जो अपने मरीजों से जुड़ सकते हैं। जीवनशैली चिकित्सा, जो शारीरिक गतिविधि, पोषण और अन्य पहलुओं के लिए साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बीमारी की रोकथाम और उपचार पर केंद्रित है, डॉक्टर और रोगी स्वास्थ्य के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा पेशेवरों को न केवल बीमारी का इलाज करने के लिए सिखाया जाए, बल्कि मरीजों और खुद दोनों के लिए स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जेनरेशन जेड चिकित्सा शिक्षा के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है चिंतनशील उपचार किस प्रकार मेडिकल छात्रों को सफलता के लिए तैयार कर सकता है प्रोग्रामेटिक मूल्यांकन के साथ बेहतर डॉक्टर बनाएं मेरे विश्वविद्यालय में, हमारी चिकित्सा शिक्षा के तीन प्रमुख स्तंभ हैं सिर (ज्ञान), हाथ (कौशल) और दिल (व्यक्तिगत और पेशेवर पहचान)। व्यक्तिगत और पेशेवर पहचान में तीन स्ट्रैंड शामिल हैं: व्यावसायिकता, नेतृत्व और लचीलापन। इन्हें पाठ्यक्रम के ताने–बाने में शामिल किया जाता है, जिससे वे छात्र प्रशिक्षण के दौरान विकसित अन्य कौशलों के बराबर स्तर पर आ जाते हैं। हम छोटी कक्षाओं में केस–आधारित शिक्षण के माध्यम से इन कौशलों को विकसित और मूल्यांकन कर सकते हैं, आदर्श रूप से 12 से अधिक लोगों वाले समूहों के साथ। इसके अलावा, ये गतिविधियाँ आत्म–जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती हैं। हमने यह भी पाया है कि प्रोग्रामेटिक मूल्यांकन, नियमित, निरंतर परीक्षण और पूरे वर्ष फीडबैक के साथ, छात्रों को विकास की मानसिकता विकसित करने और उनकी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है। इस तरह, एक बुरा दिन किसी छात्र के ग्रेड पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम कर सकता है। व्यावसायिकता पर ध्यान केंद्रित करें चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या किसी अन्य प्रकार का स्वास्थ्य पेशेवर बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा हो, वह विश्वविद्यालय में अतीत को लेकर आता है। छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि या दुनिया के हिस्सों से आते हैं, सभी अलग–अलग सांस्कृतिक और जीवन अनुभवों के साथ। व्यावसायिकता का अन्वेषण करने का अर्थ है पाठ्यक्रम के भीतर छात्रों को अपने करियर के प्रति अपनी दृष्टिकोण और वे क्या महत्व देते हैं, इस पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, चाहे वह उनके लिए हो या उनके रोगियों के लिए। यहां, हम उन्हें शिक्षण और एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें वे अपने मूल्यों, व्यवहारों, दृष्टिकोणों और व्यावसायिक संबंधों तथा रोगी सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। परिदृश्य का एक उदाहरणरू आप देखते हैं कि एक वरिष्ठ सर्जिकल प्रशिक्षु आमतौर पर अन्य टीम सदस्यों के सामने थिएटर नर्सों की आलोचना करता है, जब वे सलाह मांगते हैं या मरीजों के लिए विवरण मांगते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं असभ्य, उपेक्षापूर्ण, आलोचनात्मक और घमंडी तथा दूसरों से श्रेष्ठ हैं, तथा स्पष्ट रूप से टीम के बाकी सदस्यों को असहज महसूस कराती हैं। अपने साथियों के साथ काम करते हुए, छात्र इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार संवाद करते हैं और उनका समर्थन कैसे करते हैं? और आप इसे सहानुभूतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से कैसे कर सकते हैं? नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें परंपरागत रूप से, चिकित्सा पाठ्यक्रम नेतृत्व पर केंद्रित नहीं रहे हैं। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि मेडिकल स्कूलों में प्रभावी नेताओं की कोई कमी नहीं है, जो शिक्षण प्रक्रिया में इस मूल्य को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। एक अच्छा नेता बनना हमेशा जिम्मेदारी लेने के बारे में नहीं होता है। यह यह जानने के बारे में भी है कि कैसे सहयोग करें और अन्य लोगों के विचारों को अपनाएं, तथा यह पहचानें कि कब आपके लिए पीछे हटने का समय आ गया है और किसी और को बागडोर संभालने दें। नेतृत्व का अर्थ है संघर्ष समाधान और निर्णय लेने के लिए विभिन्न संचार शैलियों और दृष्टिकोणों पर विचार करना।

भूमि से उद्योग तक यूपी टॉप, योगी के विजन पर निवेशकों का भरोसा मजबूत

औद्योगिक भूमि के उपयोग में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में 33,327 हेक्टेयर भूमि पर संचालित हैं 286 औद्योगिक पार्क यूपी बना भरोसेमंद परिणाम देने वाला औद्योगिक गंतव्य

संवाददाता

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने देश के औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसकी झलक औद्योगिक भूमि के उपयोग के आंकड़ों में दिखाई देती है। कई प्रमुख राज्यों में औद्योगिक पार्कों की बड़े क्षेत्रफल में भूमि आज भी निष्क्रिय पड़ी है, वहीं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई गई औद्योगिक भूमि का अधिकांश हिस्सा उद्योगों के लिए उपयोग हो चुका है। 286 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की सक्रियता स्पष्ट करती है कि निवेश प्रस्ताव केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहे। देश और विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश को एक भरोसेमंद और परिणाम देने वाले औद्योगिक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। उद्योग जगत के विशेषज्ञ एसके आहूजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के बड़े औद्योगिक पावरहाउस के रूप में उभर रहा है।उत्तर प्रदेश में 286 विकसित औद्योगिक पार्कों का कुल क्षेत्रफल 33,327 हेक्टेयर है। इनमें लगभग पूरी औद्योगिक भूमि पर उद्योग या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापना की प्रक्रिया में हैं। जहाँ उत्पादन गतिविधियों को बल मिल रहा है और वहीँ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का भी सृजन हो रहा है। यदि देश के अन्य राज्यों की स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि तेलंगाना में 157 औद्योगिक पार्कों में 30,749 हेक्टेयर भूमि आज भी निवेश के लिए उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति को स्पष्ट दिशा प्रदान करने का काम किया है। सरकार का फोकस केवल भूमि आवंटन पर ही नहीं वरन उद्योगों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण देने पर भी रहा है। कानून–व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण और बुनियादी ढांचे का तेज विस्तार इस नीति के मुख्य स्तंभ बने। एक्सप्रेस–वे, एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी ने उद्योगों के संचालन को आसान बनाया जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।एक जनपद, एक उत्पाद ओडीओपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल हब जैसी योजनाओं ने औद्योगिक विकास को केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहने दिया। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उद्योग स्थापित हुए हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और क्षेत्रीय असमानता में कमी आई है। राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश आज ठोस परिणामों के साथ अग्रणी प्रदेश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अब उद्योगों को गति देने के लिए 'प्लग एंड प्ले' मॉडल पर विशेष जोर दे रही है। इसके अंतर्गत निवेशकों को पहले दिन से ही तैयार अवसंरचना मिलेगी। यही मॉडल उत्तर प्रदेश को औद्योगिक मामले में अन्य राज्यों से आगे लेकर जाएगी।

बंद गाड़ियों से होगा कचरा ढुलाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में पीसीटीएस का महापौर ने किया उद्घाटन

संवाददाता

लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने शनिवार को अलीगंज सेक्टर–एल में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (पीसीटीएस) का उद्घाटन किया। इससे खुले में कचरा नहीं फेंका जाएगा। दुर्गंध की समस्या से राहत मिलेगी। महापौर ने ने स्वच्छता में साथ देने की अपील की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड के यादव लोहा भंडार परिसर में बने इस स्टेशन के शुभारंभ पर पार्षद मान सिंह यादव, नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि आधुनिक तकनीक से शहर को स्वच्छ–सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से कचरा नगर निगम के गाड़ियों को ही देने की अपील की है। साथ ही शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। नगर आयुक्त ने बताया कि लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रालि को 5 जोनों में कूड़ा कलेक्शन और साफ सफाई का काम सौंपा गया है। इसमें डोर–टू–डोर संग्रहण, सड़क सफाई और पीसीटीएस शामिल। शहर में कुल 32 साइटें बनेंगी। पहले चरण की 8 और दूसरे की 24। अब तक 21 साइटें शुरू हो चुकी हैं। बाकी मार्च 2026 तक तैयार होगी। इसके बनने से बंद गाड़ी में कचरे की ढुलाई होगी। इस पीसीटीएस में 2 हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर (20 घन मीटर प्रत्येक) लगे हैं। हाइवा वाहन और भारत बेंज ट्रक से कचरा पहुंचेगा प्रोसेसिंग यूनिट तक। इससे खुले कचरा, बिखराव रुकेगा और निस्तारण तेज होगा।

बिजनौर में प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने किया उद्घाटन

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बिजनौर में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू हो गया। शनिवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। अब लोग शादी से पहले यहां आकर वैवाहिक जीवन से जुड़ी परामर्श ले सकेंगे। सेंटर सरवननगर स्थित राम विहार कॉलोनी में बना है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम आधारशिला संस्थान में रखा गया।

बबीता चौहान ने फीता काटकर सेंटर की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि विवाह से पहले परामर्श लेना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के माध्यम से युवाओं को वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों, आपसी समझ, संवाद और समर्पण का महत्व समझाया जा सकता है। इससे भविष्य में होने वाले विवादों और टूटते रिश्तों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। उन्होंने इस पहल को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और दूरदर्शी बताया। कार्यक्रम में आधारशिला संस्थान के अध्यक्ष गोस्वामी शशांक भारती ने संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह केंद्र युवाओं को विवाह से पहले मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने का कार्य करेगा। इस दौरान काउंसलर आकांक्षा, अमित, प्रखर, सतेंद्र और आकाश ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान ही बिजनौर थाने की ओर से मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तीकरण से संबंधित जानकारी दी गई। इस जागरूकता गोष्ठी में सब–इंस्पेक्टर आराधना वर्मा और सब–इंस्पेक्टर रामराज सिंह सहित महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया। आधारशिला संस्थान द्वारा शुरू किया गया यह प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर समाज में स्वस्थ, संतुलित और सशक्त वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थान से जुड़े लोग मौजूद रहे।

नए साल की शुरुआत पर होम क्रेडिट इंडिया ने पेश की पहली एआई जनरेटेड फिल्म

संवाददाता

लखनऊ। अग्रणी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, होम क्रेडिट इंडिया ने आज अपने पहले एआई आधारित कैंपेन रुसपनों का नया साल को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कैंपेन उनके ब्रांड विचार रुजिंदगी हिट! का ही एक विस्तार है। यह होम क्रेडिट इंडिया के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे ए आर एम वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर एक सिनेमैटिक फिल्म के रूप में विकसित किया गया है, जो बीते हुए साल की यादों को समेटते हुए आशाओं से भरे भविष्य का स्वागत करती है। यह फिल्म ब्रांड को एक टेक–फॉरवर्ड और भरोसेमंद साथी के रूप में पेश करती है, जो देश भर के ग्राहकों की विविध आकांक्षाओं को कभी भी और कहीं भी पूरा करने के लिए तैयार है। यह नया कैंपेन होम क्रेडिट इंडिया के सोशल मीडिया चौनलों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गया है। रुसपनों का नया साल कैंपेन बीते साल की हर छोटी–बड़ी उपलब्धि को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, यह ग्राहकों को आसान और सुलभ क्रेडिट समाधानों के माध्यम से उनके नए साल के संकल्पों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाता है। कैंपेन की कथावस्तु वीडियो की शुरुआत नए साल के आगमन के आखिरी कुछ मिनटों से होती है, जिसमें सपनों और जिम्मेदारियों के बीच के आम मानवीय पलों को दर्शाया गया है। इसमें रवि है, जो एक युवा डिलीवरी एक्जीक्यूटिव है और अपने खराब होते स्कूटर से परेशान हैय गौरव एक महत्वाकांक्षी उद्यमी है जो फंड की कमी के कारण पीछे रुका हुआ हैय आरव टूटे हुए फोन के साथ रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना कर रहा हैय और प्रीति, जो एक कैफे मालकिन है और अपने पुराने कैफे के नवीनीकरण का सपना देख रही है। जैसे ही घड़ी में बारह बजते हैं, होम क्रेडिट से मिलने वाली लोन अप्रूवल की पिंग (नोटिफिकेशन) एक दूसरे से जुड़ी इन कहानियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। यह उनकी तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक आकांक्षाओं, दोनों को पूरा करती है। एक तेज रफ्तार मोंटाज के जरिए रुके हुए पल नई शुरुआत में बदल जाते हैंकृ रवि को नया स्कूटर मिलता है, गौरव अपना व्यवसाय शुरू करता है, आरव अपना फोन अपग्रेड करता है और प्रीति अपने कैफे का कायाकल्प करती है। कहानी उम्मीद के एक साझा पल के साथ समाप्त होती है, जो यह साबित करती है कि सही सहयोग के साथ हर संकल्प को पूरा करना संभव है। नये साल के कैंपेन पर बात करते हुए, होम क्रेडिट इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आशीष तिवारी ने कहा, ष्एक और साल के बीतने के साथ, हम नवाचार, कृतज्ञता और ढेर सारी उम्मीदों के साथ नए साल में कदम रख रहे हैं। रुसपनों का नया साल के माध्यम से, हम होम क्रेडिट इंडिया को एक ऐसे उत्प्रेरक के रूप में पेश करना चाहते हैं जो साल के अंत की कृतज्ञता और नए साल के संकल्पों को हकीकत में बदल देता है। इन कहानियों को बताने के लिए एआई का उपयोग करके, हम अपने ग्राहकों की आधुनिक और डिजिटल–फर्स्ट यात्रा को दर्शाते हैं। हमारे सरल और ग्राहक–अनुकूल फाइनेंस विकल्प यह सुनिश्चित करते हैं कि संकल्प पूरे किए जाएंकृचाहे वह पुराने फोन को बदलना हो, किसी जगह का नवीनीकरण करना हो, सपनों का व्यवसाय शुरू करना हो या दोपहिया वाहन खरीदना हो। वित्तीय सहायता से परे, हमारा ध्यान हर उस ग्राहक में गर्व और आत्मविश्वास जगाने पर है जिसकी हम सेवा करते हैं, और एक भरोसेमंद वित्तीय भागीदार के रूप में उनके साथ चलते हुए हर रुसपनों का नया साल बनाना है।ष रुसपनों का नया साल के साथ, होम क्रेडिट इंडिया हर किसी के लिए, कभी भी वित्तीय समाधानों को सुलभ और सुविधाजनक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

संक्षिप्त

हाउस टैक्स कलेक्शन की रफ्तार धीमी, रविवार को खुलेंगे कार्यालय

संवाददाता

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लक्ष्य पूरे करने के लिए नगर निगम ने हाउस टैक्स कलेक्शन की रफ्तार बढ़ा दी है। दिसंबर के आखिरी दिनों में वसूली धीमी रहने पर नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब रविवार 28 दिसंबर को भी नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय और कैश काउंटर खुले रहेंगे, ताकि लोग बिना दिक्कत अपना गृहकर जमा कर सकें। रविवार को जोनल कार्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान कर निर्धारण, फीडिंग और गृहकर से जुड़े अन्य कार्य किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि कई जोनों में पिछली बार की तुलना में दिसंबर की वसूली कम रही है। इस पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बकायेदार भवन स्वामियों से सीधे संपर्क किया जाए। समय रहते ठोस कदम उठाने से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि नागरिकों को कर भुगतान में सहूलियत भी मिलेगी। नगर निगम सभी वार्डों में विशेष कर वसूली कैंप भी लगाएगा। यहां मौके पर ही कर निर्धारण, संशोधन और भुगतान की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने इन कैंपों के व्यापक प्रचार का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इनका लाभ उठा सकें। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि वसूली से जुड़े निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जयंत चौधरी युवाओं, किसानों एवं छात्रों की सशक्त आवाज : रालोद

संवाददाता

लखनऊ। केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल छात्रसभा द्वारा हनुमान सेतु मंदिर में विशेष पूजा–अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पाण्डेय एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने जयंत चौधरी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल राजनीतिक जीवन की कामना करते हुए विधिवत पूजा–अर्चना की।पूजा–अर्चना के उपरांत हनुमान सेतु परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजन ने प्रसाद ग्रहण किया।

बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन

पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर आदेशों के उल्लंघन का आरोप

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठन ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन का आरोप है कि कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही पूर्व जारी आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, जिससे 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन और अनुरक्षण कार्य में तैनात लगभग 15 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने 15 मई 2017 के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों की छंटनी की है। इसके साथ ही, मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई और 18 सितंबर 2025 के आदेश के अनुसार कार्य के अनुरूप अनुबंध भी नहीं किया गया। कर्मचारियों के लिए 18,000 का न्यूनतम वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया है। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को अब तक कार्य पर वापस नहीं लिया गया है। संगठन ने घायल कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा न मिलने, उपचार पर खर्च की गई राशि का भुगतान संविदाकारों के बिल से न किए जाने का भी विरोध किया। इसके अलावा, 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर अनुभवी कर्मचारियों को हटाने का भी विरोध किया जा रहा है। बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर 18 सितंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने पर भी सहमति बनी थी। इसके साथ ही, घायल कर्मचारियों के इलाज पर खर्च की गई राशि की जांच कर

इसमें 15 मई 2025 के आदेशों का उल्लंघन कर किसी भी कर्मचारी को न हटाना, 55 वर्ष के आधार पर हटाए गए कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करना और वर्टिकल व्यवस्था लागू होने पर भी किसी कर्मचारी की छंटनी न करना शामिल भुगतान करने और मीटर रीडरों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान की जांच करने पर भी सहमति बनी थी।हालांकि, संगठन का आरोप है कि 29 नवंबर 2025 को जारी किया गया कार्यवृत्त (मिनट्स), 26 नवंबर की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप नहीं है।

किसान के घर लाखों की चोरी,पीछा करने पर 2 राउंड फायरिंग की

संवाददाता

लखनऊ। बीकेटी थाना क्षेत्र के रैथा गांव में किसान के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। देर रात परिवार के सोने की तैयारी कर रहा था, तभी घर के भीतर संदिग्ध आवाजों से हड़कंप मच गया। चोर घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी समेट ले गए। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रैथा गांव निवासी किसान रामू सिंह के घर शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात करीब 1.30 से 2 बजे के बीच चोर छत के रास्ते दाखिल हुए। चोर सीधे उस कमरे तक पहुंचे, जहां परिवार का कीमती सामान रखा हुआ था। कमरे का ताला तोड़कर उन्होंने अलमारियों में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।रामू सिंह ने बताया कि जब वे परिवार के साथ सोने जा रहे थे, तभी एक कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी।

लखनऊ जेल में बंद युवक की मौत, बहन बोली, पुलिस ने गिराकर सीने पर लातें मारीं

संवाददाता

लखनऊ। चोरी के आरोप में लखनऊ जेल में बंद एक युवक की मौत हो गई। उसे पुलिस ने बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया था। बाद में परिजन को फोन कर सूचना दी कि जल्दी अस्पताल पहुंचो। वहां पहुंचे परिजन को युवक की डेडबॉडी मिली। इस पर उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे बहुत मारा–पीटा था। गिराकर सीने पर लातें मारीं। जब उसकी हालत बिगड़ी तब अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान सीतापुर के मिथुन कुमार (28) पुत्र चंद्रिका प्रसाद के रूप में हुई। वह आशियाना थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी के मामले में आरोपी था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 26 दिसंबर को घरवाले जेल में मिलने गए थे। तब उसने बताया था कि चौकी में बहुत पिटाई की गई। पुलिस ने सीने पर लातों से कुचला था। बहुत दर्द हो रहा है। इलाज नहीं करवाया जा रहा है। युवक मिथुन अपनी पत्नी नैना देवी और दो बच्चों के साथ आशियाना के रश्मिखंड, बंगला बाजार में किराये के मकान में रहता था। इलाके में लाइटिंग का काम करके गुजर–बसर कर रहा था। रतनखंड में अनिल सिंह के मकान में लाइटिंग का चल रहा था। उसी दरम्यान 29 नवंबर को अनिल के घर में चोरी हो गई। उसकी शिकायत अज्ञात के खिलाफ थाने में लिखवाई गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों शाहरुख और अब्दुल को पकड़ा। उन दोनों की निशानदेही पर मिथुन को 16 दिसंबर को अनिल सिंह के घर से गिरफ्तार किया। वह उस समय भी अपना काम कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद परिजन उससे मिलने 26 दिसंबर को गए थे तो उसने पूरी आपबीती उन्हें सुनाई थी। बड़ी बहन मनोरमा ने बताया कि 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे मिथुन काम पर निकला। उसके बाद उससे संपर्क किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात करीब 8 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद आसपास तलाश करने पर जानकारी नहीं मिली। आशियाना थाने जाकर पूछा तो वहां से भी कुछ नहीं बताया। तीन दिन तलाश करने के बाद कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने डायल–112 पर फोन किया। उसके बाद थाने से बताया गया कि पुलिस ने भाई मिथुन और उसके साथ काम करने वाले नाबालिग को पकड़ा है। 19 दिसंबर को मिथुन के थाने में होने की जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। भाई मिथुन के साथ वाले नाबालिग को छोड़ दिया। पुलिस दोनों को आशियाना से पकड़ने के बाद चौकी लेकर गई। वहां डंडे और बेल्टों से बेहरमी से पीटा।

कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 20 जनवरी को घेरेंगे विधानसभा

संवाददाता

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव कार्मिक एवं विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए वार्ता तक नहीं कर रहे हैं।संयुक्त परिषद ने अगस्त में प्रदेश के मुख्य सचिव को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए 3 सितंबर तक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने की मांग किया था, परंतु शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर लगातार मौन साधे हुए हैं। कर्मचारी संगठन एवं शासन के बीच संवाद हीनता आंदोलन का कारण है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन कर दिया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, परंतु उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार ठेकेदारी प्रथा एवं संविदा कर्मचारियों के भरोसे पूरा सिस्टम चलाने का प्रयास कर रही है। संविदा कर्मियों एवं ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। संविदा कर्मियों को मनमाने तरीके से बाहर किया जा रहा है।नगरीय परिवहन सेवाओं में कार्यरत हजारों कर्मचारियों से सरकार रोजगार छीन चुकी है ,जबकि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने इस संदर्भ में परिषद द्वारा भेजे गए दर्जनों पत्रों का संज्ञान तक नहीं लिया है। समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग में विगत दो वर्षों में दो दर्जन से अधिक संविदा शिक्षक नौकरी से हटाए जा चुके हैं। यही स्थिति अन्य विभागों की भी है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर मुख्य सचिव समिति निर्णय नहीं कर रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में विगत कई वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाने, 2001 के बाद संविदा, वर्क चार्ज एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी–शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने, सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण रोके जाने, सहित संयुक्त परिषद की 5 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए संयुक्त परिषद 3 सितंबर से विभिन्न चरणों में आंदोलन कर रही है।संयुक्त परिषद शासन एवं कर्मचारियों के बीच सद्भाव का वातावरण बनाकर कार्य करना चाहती है, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद हीनता के कारण 20 जनवरी को विधान सभा पर प्रदर्शन का कार्यक्रम अपरिहार्य हो गया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।

संदिग्ध परिस्थितियों में कैटर्स की मौत, दोस्त के साथ नेपाल घूमने गया

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमनगर पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैटर्स का शव मिला। मृतक 21 दिसंबर को अपने दोस्त के साथ नेपाल घूमने गया था। 30 दिसंबर को लौटकर आना था, लेकिन 5 दिन पहले ही 26 दिसंबर को उनका शव मिला। परिजन का आरोप है कि मृतक के पास से एक बैग और पर्स गायब हैं। साथ में गए दोस्त का कोई पता नहीं चल रहा है। मृतक की पहचान पारा निवासी करण गुप्ता (49) के रूप में हुई। वह इलाके में कैटरिंग का काम करते हैं। उनके दो बेटे आयुष और ईशू हैं। वहीं, पत्नी रीना गुप्ता कई दिनों से मायके में हैं। करण अपने दोस्त अनुज के साथ 21 दिसंबर को नेपाल घूमने गए थे। भांजे विशाल गुप्ता ने बताया कि उस दिन मामा का दोस्त अनुज घर आया था। उसने पहले कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। मामा उसके साथ चले गए। दूसरे दिन मामा का सुबह फोन आया। उन्होंने बताया कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हैं। फिर 23 दिसंबर को वॉट्सऐप कॉल आया। इस बार उन्होंने बताया कि अनुज कोई फ्रॉड करके भागा है इसलिए नेपाल में रुका है। उसके साथ के कई लोग फरार हैं। इसके बाद मैंने उनसे लखनऊ आने की बात कही तो वह बोले कोई दिक्कत नहीं है। शाम को करीब 3.00 बजे मामा के नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि मामा विक्रमनगर पुल के नीचे बेहोश पड़े हैं। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे तो उन्हें एम्बुलेंस से लोकबंधु अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनकी मौत हो गई है। मामा घर से निकले थे तो उनके पास एक बैग और पर्स था जिनमें तमाम दस्तावेज और पैसे थे। विशाल ने बताया कि मामा की मौत के बाद जब उनके दोस्त अनुज को फोन मिलाया तो मिला नहीं, पता करने पर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि ऐसा लग रहा कि हार्टअटैक से मौत हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। परिजन ने अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों का योगदान अद्वितीय - मुख्यमंत्री साय

शहीद गैंद सिंह नायक ने किया स्वाधीनता आंदोलन का सर्वप्रथम शंखनाद
हल्बा–हल्बी समाज के शक्ति दिवस पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री
समाज के नवनिर्मित कार्यालय भवन के लोकार्पण सहित कई घोषणाएं

बीएनई

रायपुर। स्वाधीनता आंदोलन के साथ–साथ राष्ट्र व समाज के नवनिर्माण में आदिवासी नायकों एवं महापुरूषों का अद्वितीय योगदान है। हल्बा, हल्बी एवं आदिवासी समाज सहित संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव शहीद गैंद सिंह नायक ने हमारे देश में आजादी का आंदोलन का सर्वप्रथम शंखनाद किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जिला मुख्यालय दुर्ग के गोकुल नगर स्थित हल्बा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हल्बा–हल्बी समाज द्वारा आयोजित 35वां मिलन समारोह एवं शक्ति दिवस पर्व को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर हल्बा–हल्बी समाज के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण भी किया। साय ने शक्ति स्थल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हल्बा समाज के युवा–युवतियों को आवासीय कोचिंग सुविधा प्रदान करने हेतु 50 लाख रूपए तथा पुलगांव दुर्ग स्थित कंवर समाज के सामाजिक भवन में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु 25 लाख रूपए की स्वीकृत किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने हल्बा–हल्बी समाज के सामाजिक पत्रिका 'समाज' का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आजादी के आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम जनजातीय समाज के नायको ने किया था। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह नायक सहित जनजाति नायकों एवं देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 14 क्रांतियों का शंखनाद किया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी ने जनजाति वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए सर्वप्रथम केन्द्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय का गठन भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राजधानी रायपुर में जनजाति समाज के नायकों एवं वीर सपूतों के योगदान तथा अमर गाथाओं को नई पीढ़ी को परिचित कराने साथ–साथ उसके संरक्षण और संवर्धन हेतु विशाल आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की अधिकांश गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया है। राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रूपए प्रति बोरा के हिसाब से पारिश्रमिक तथा किसानों को धान का मूल्य 3100 रूपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। 26 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी दी गई है। राज्य में भी नक्सलवाद अपने अंतिम सांस गिन रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से 400 से अधिक गांवों में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, हल्बा–हल्बी समाज के प्रदेश अध्यक्ष खलेन्द्र ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ललित चन्द्राकर, अखिल भारतीय हल्बा–हल्बी समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1000 रन और 150 विकेट लेकर बनीं पहली भारतीय क्रिकेटर

एजेंसी

तिरुवनंतपुरम। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस मैच में उन्होंने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली तीसरी खिलाड़ी बनने की उपलब्धि के साथ इसी प्रारूप में एक हजार रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने का भी कारनामा किया। वह इस प्रारुप में (महिला, पुरुष) दोनों में यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है। ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को दीप्ति के 3ध्18 के शानदार स्पेल से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महान एलिस पेरी को पीछे छोड़ दिया है। पेरी ने 271 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 331 विकेट थे। दीप्ति के नाम अब 333 विकेट हो गए हैं। यह कारनामा करने वालों में वह अब केवल इंग्लैंड की कैथरीन

साइवर–ब्रंट और भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी से पीछे हैं। 26 साल की दीप्ति ने इस छोटे फॉर्मेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। वह टी–20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर (पुरुष या महिला) खिलाड़ी बन गईं। दीप्ति ने श्रीलंका की कविशा दिलहारी को आउट करके यह मुकाम हासिल किया और बाद में अपना 151वां टी–20 विकेट लिया, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के साथ महिला टी–20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। महिला एकदिवसीय में, वह झूलन गोस्वामी के बाद भारत की दूसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 121 मैचों में 162 विकेट लिए हैं, जबकि पांच टेस्ट मैचों में 18.10 के शानदार औसत से 20 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने अब इस प्रारुप में 1,100 से अधिक रन बनाए हैं और 151 विकेट भी लिए हैं। वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में टी–20 के इतिहास में एक हजार रन और 150 विकेट का कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी हैं।

भारत वैश्विक मंच पर उभरती ताकत, 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर, बोले ब्रिटिश पीएम

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत–ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पिछले चार वर्षों से काम जारी था और यह 2025 में आकार ले सका। स्टार्मर ने संसद में कहा, भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती ताकत है और 2028 तक

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर है। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम ने कहा–व्यापार और निवेश से आगे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देने के लिए 'विजन 2035' समझौते पर भी सहमति बनी। एफटीए को लेकर वार्ताएं वर्ष के ज्यादातर समय सुर्खियों में रहीं। दोनों पक्ष समझौते के लिए प्रतिबद्ध दिखे और जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने मोदी से हुई द्विपक्षीय चर्चा के बाद कहा, हमने दुनिया की तेज अर्थव्यवस्था भारत के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। उन्होंने अक्तूबर में अब तक के सबसे बड़े ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत यात्रा का निमंत्रण भी स्वीकार किया। दीर्घकालिक सहयोग की राह भी खुलेगी 2025 में दोनों देशों के महत्वाकांक्षी व भविष्य–उन्मुख 10 वर्षीय भारत–ब्रिटेन विजन 2035 रोडमैप को भी रखा गया। यह दीर्घकालिक सहयोग और नवाचार के रणनीतिक लक्ष्य तय करता है। ब्रिटेन के उच्च शिक्षा क्षेत्र की भारत में बढ़ती मौजूदगी भी नए वर्ष से फलीभूत होगी। नौ ब्रिटिश विवि भी भारत में अपने विदेशी परिसरों को अंतिम रूप दे रहे हैं। अगले साल सीईटीए को ब्रिटिश संसद की मंजूरी संभावित ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग (डीबीटी) के विश्लेषण के अनुसार, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) लागू होने पर द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 44.1 अरब पाउंड से बढ़कर कई अरब पाउंड से अधिक हो सकता है। उम्मीद है कि 2026 की पहली छमाही में समझौते को ब्रिटिश संसद की मंजूरी मिल जाएगी, जिसका दोनों देशों को परस्पर लाभ होगा। अध्ययन वीजा पर रुझान बढ़ेगा हालिया आंकड़ों के अनुसार, अध्ययन वीजा पर करीब 45,000 भारतीय और कामकाजी वीजा पर 22,000 पेशेवर देश से बाहर गए, जिससे वहां शुद्ध आव्रजन में कमी आई। स्थायी निवास के लिए प्रतीक्षा अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने जैसे सख्त नियमों से यह रुझान आगे भी बना रह सकता है। आतंकवाद पर भारत–ब्रिटेन साथ–साथ भारत–ब्रिटेन संबंधों में आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता भी प्रमुख रही। नवंबर में दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर ब्रिटेन ने संवेदना जताई और अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया।

सरकारी बैंकों के विलय में अगले साल तेजी, बनेंगे बड़े बैंक; वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मिलेगी मजबूती

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार 2047 तक विकसित भारत के विकास के अगले चरण को रफ्तार देने के लिए देश में बड़े बैंकों की दिशा में काम तेजी से शुरू कर दिया है। अगले साल से इसका नतीजा दिखने भी लगेगा। छोटों को बड़े बैंकों में मिलाकर वैश्विक स्तर के चार–पांच बैंक बनाए जाने की योजना है। इससे घरेलू बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत को कई बड़े, विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस समय 12 सरकारी बैंक हैं। देश का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एकमात्र बैंक है जो परिसंपत्तियों के आधार पर वैश्विक शीर्ष–50 बैंकों में शामिल है। यह 43वें स्थान पर है। निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक 73वें स्थान पर है। बड़े बैंकों के निर्माण के उद्देश्य से सरकार ने पहले दो बार विलय प्रक्रिया चलाई थी। अगस्त, 2019 में चार बड़े बैंकों के विलय की घोषणा की गई। इससे इनकी कुल संख्या

2017 के 27 से घटकर 12 हो गई। 1 अप्रैल, 2020 से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में व इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। दो लाख करोड़ तक हो सकता है फायदा मौजूदा रुझान को देखते हुए सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ 2025–26 के अंत तक 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। 2024–25 में यह रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये था। 2023–24 में 1.41 लाख करोड़ रुपये इन बैंकों ने कमाए थे।

संक्षिप्त

सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में बनाया दबदबा, सीनियर–जूनियर दोनों में बने विजेता

एजेंसी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चौंपियनशिप में शुक्रवार को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल (आरएफपी) स्पर्धा के सीनियर और जूनियर दोनों पुरुष वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। सूरज ने सीनियर फाइनल में अपने पहले 20 में से 19 को सटीक निशाने लगाते हुए शानदार शुरुआत की। उन्होंने 31 निशाने लगाकर प्रतियोगिता का समापन किया। सूरज ने पंजाब के मौजूदा चौंपियन विजयवीर सिद्धू (28) को तीन अंकों से पछाड़ा। राजस्थान के भावेश शेखावत ने 24 निशानों के साथ कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले क्वालीफाइंग चरण में अंकुर गोयल ने 582–20एक्स के मजबूत स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनके ठीक

पीछे विजयवीर थे जिन्होंने 580–18एक्स का स्कोर किया जबकि आदर्श सिंह 579–22एक्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सूरज 579–12एक्स के साथ पांचवें स्थान पर क्वालिफाई करने में सफल रहे। इससे पहले आरएफपी जूनियर पुरुष फाइनल में सूरज ने संयमित प्रदर्शन करते हुए 30 निशाने के साथ स्वर्ण पदक जीता। मुकेश ने 25 निशाने के साथ रजत पदक हासिल किया। हरियाणा के जतिन को शूटऑफ के बाद 22 निशाने के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
सीनियर टीम वर्ग में विजयवीर, उदयवीर सिद्धू और राजकंवर सिंह संधू के नेतृत्व में पंजाब ने 1725 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा ने आदर्श सिंह, मनदीप सिंह और समीर के संयुक्त प्रयासों से 1722 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया जबकि नौसेना ने प्रदीप सिंह शेखावत, रजत कुमार यादव और ओंकार सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 1711 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।

अगरबत्ती में खतरनाक रसायनों पर लगेगी लगाम, सरकार ने तय किए नए गुणवत्ता मानक

एजेंसी

नई दिल्ली। हर घर में उपयोग होने वाली अगरबत्ती में खतरनाक रसायन मिलने की जानकारी सामने आई है। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नया गुणवत्ता मानक पेश किया है। इस नए मानक से 8,000 करोड़ रुपये के उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत अगरबत्ती का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। उपभोक्ता सुरक्षा और नियामक अनुपालन पर बढ़ते जोर के साथ कुछ सुगंधित तत्वों और रसायनों पर वैश्विक प्रतिबंधों को देखते हुए अगरबत्ती के लिए एक विशेष भारतीय मानक आईएस 19412:2025 विकसित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नए मानक का पालन करने वाले उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न भी लगाया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को सोच–समझकर और विश्वास के साथ चुनाव करने में मदद मिलेगी।

विजय हजारे में विराट-रोहित की सैलरी कितनी? स्टार हों या डेब्यूटेंट, सबके लिए BCCI के नियम एक जैसे

एजेंसी

मुंबई। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और आईपीएल में करोड़ों रुपये कमाते हैं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों को उनकी स्टार वैल्यू के आधार पर नहीं, बल्कि तयशुदा नियमों के तहत भुगतान किया जाता है। यहां कोई ऑक्शन नहीं होता, बल्कि अनुभव ही सबसे बड़ा पैमाना होता है।
विजय हजारे ट्रॉफी का सैलरी स्ट्रक्चर (2025–26)
बीसीसीआई ने 2025–26 सीजन के लिए खिलाड़ियों की सैलरी को तीन श्रेणियों में बांटा है, जो उनके द्वारा खेले गए लिस्ट–ए मैचों की संख्या पर आधारित है।
सीनियर कैटेगरी (40 से ज्यादा लिस्ट–ए मैच):
प्लेइंग इलेवन में मौजूद खिलाड़ी को : 60,000 रुपये प्रति मैच
रिजर्व खिलाड़ी को: 30,000 रुपये प्रति मैच
मिड–लेवल कैटेगरी (21–40 मैच):
प्लेइंग इलेवन में मौजूद खिलाड़ी को : 50,000 रुपये प्रति मैच
रिजर्व खिलाड़ी को : 25,000 रुपये प्रति मैच
जूनियर कैटेगरी (0–20 मैच):
प्लेइंग इलेवन में मौजूद खिलाड़ी कोरू 40,000 रुपये प्रति मैच
रिजर्व खिलाड़ी कोरू 20,000 रुपये प्रति मैच
विराट और रोहित को कितने पैसे मिलते हैं?
विराट कोहली (दिल्ली) और रोहित शर्मा (मुंबई) दोनों ही 40 से अधिक लिस्ट–ए मैच खेल चुके हैं, इसलिए वे सीनियर कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में 60,000 रुपये प्रति मैच मिलते हैं, जो कि किसी भी अनुभवी घरेलू खिलाड़ी के बराबर है। अभी तक दोनों दो–दो मैच खेल चुके हैं। यानी दोनों एक लाख 20 हजार रुपये की सैलरी बना चुके हैं। तुलना करें तो बीसीसीआई इन दोनों को एक अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेलने के लिए लगभग छह लाख रुपये देता है, यानी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैच फीस में जमीन–आसमान का फर्क है। मैच फीस के अलावा और क्या मिलता है? विजय हजारे ट्रॉफी में कमाई सिर्फ मैच फीस तक सीमित नहीं रहती। खिलाड़ियों को डेली अलाउंस (यात्रा, खाना और ठहरने के लिए), परफॉर्मेंस बोनस (मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड बनने पर आमतौर पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं) और प्राइज मनी (नॉकआउट और फाइनल खेलने वाली टीमों के लिए) भी मिलती है। अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ी अपनी कुल कमाई बढ़ा सकते हैं। हालांकि, रोहित और कोहली ने अब तक विजय हजारे में शानदार प्रदर्शन किया है और इसके दम पर वे इस टूर्नामेंट में अधिक कमाई भी कर सकते हैं।

औपनिवेशिक कानून हटे, इंस्पेक्टर राज खत्म, कारोबार को मिली नई रफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के आर्थिक इतिहास में वर्ष 2025 ऐसी विनियमन क्रांति लेकर आया जिसने न केवल कारोबार करना और सुगम बनाया बल्कि उन्हें बिना किसी बाधा के विस्तार का मौका भी दिया। तमाम उपनिवेशकालीन कानून खत्म होने से भारत में व्यापार करना अब किसी बाधा दौड़ जैसा नहीं रहा। वर्ष 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए द्वार खोले थे तो 2025 के सुधारों ने कारोबारियों को सरकारी लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज के डर से आजाद कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सत्ता शीर्ष ने स्पष्ट तौर पर एक ही मंत्र अपना रखा है। व्यापारियों को कागजी खानापूरी के जाल में उलझाने के बजाय बेझिझक आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। पुराने कानूनों को खत्म करने और नियमों को सरल बनाने का ही नतीजा है कि आज भारत में कंपनियों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है और दुनियाभर के निवेशक भारत को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार की नीतियों में बदलाव से भारत में व्यापार करना अब एक सुखद अनुभव बन गया है जबकि 2010 के दशक की शुरुआत में भारत में व्यापार करना किसी बाधा दौड़ जैसा होता था।

जनवरी 2026 में क्यों री-रिलीज होगी किस किसको प्यार करूं 2 ? कपिल की फिल्म के मेकर्स ने बताई ये बड़ी वजह

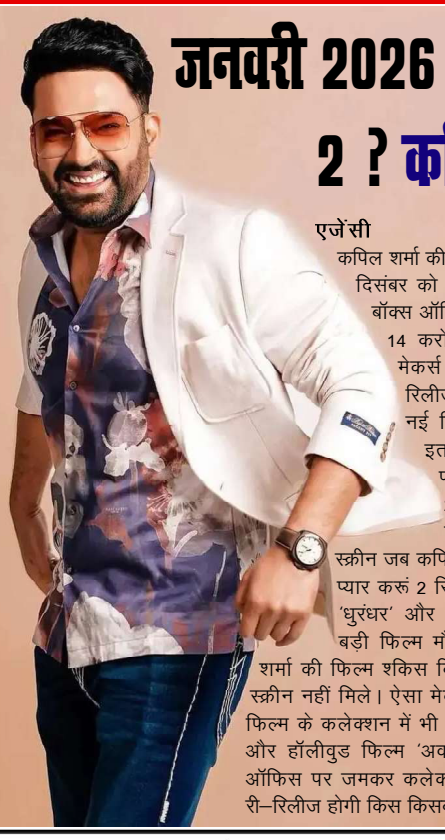

एजेंसी

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी। कुछ दिन में ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस से उतर गई। फिल्म ने इंडिया में ग्रास 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। अब इसके मेकर्स ने फिल्म को अगले साल जनवरी महीने में रिलीज करने की बात कही है। जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट भी मेकर्स शेयर करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी फिल्म को री–रिलीज करने का फैसला 'किस किसको प्यार करूं 2' मेकर्स ने क्यों लिया है, जानिए?
बड़ी फिल्मों के कारण नहीं मिले स्क्रीन जब कपिल शर्मा की फिल्म शकिस किसको प्यार करूं 2 रिलीज हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'अवतार–फायर एंड ऐश' जैसी बड़ी फिल्म मौजूद थीं। इस वजह से कपिल शर्मा की फिल्म शकिस किसको प्यार करूं 2 को मनचाहे स्क्रीन नहीं मिले। ऐसा मेकर्स का कहना है। इस वजह से फिल्म के कलेक्शन में भी कमी दिखी। बता दें कि 'धुरंधर' और हॉलीवुड फिल्म 'अवतार–फायर एंड ऐश' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन किया है।
री–रिलीज होगी किस किसको प्यार करूं 2 किस किसको प्यार करूं 2 के प्रोड्यूसर रतन जैन ने अब कपिल की फिल्म को री–रिलीज करने का फैसला लिया है। जनवरी 2026 में कपिल की फिल्म री–रिलीज होगी। नई रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी। क्या थी कपिल शर्मा की फिल्म की कहानी कपिल शर्मा किस किसको प्यार करूं 2 में लीड रोल में थे। इनके अलावा आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और मनजोत सिंह ने अहम किरदार निभाए। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी ऐसे इंसान की है, जो गलतफहमी में चार लड़कियों से शादी कर लेता है। इसके बाद फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743